551वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 17 फरवरी, 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 551 दिनांक 17/02/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक एजेण्डा क्रमावार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों के तकनीकी परीक्षण किया गया ।

1. प्रकरण क्रमांक 8476/2021 श्री पदम् भार्गव, नवमहिला घासमंडी जिला ग्वारियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1354 रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,50,001 मी.^{3}, ग्राम खरग तहसील एवं जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1354 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम खरग तहसील एवं जिला दतिया (म.प्र.) पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 497वीं दिनांक 05/04/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान पहाड़ के ऊपर स्थित है जिसके चारों ओर अन्य खदानें कार्यरत है । खदान के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी दिशा में स्टोन क्रेशर्स

कार्यरत है। खदान के उत्तर दिशा में लीज बाउण्ड्री से लगी हुई एक कच्ची रोड़ 7.5 मीटर पर है जो क्रेशर तक पहुॅच मार्ग है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनकी खदान कार्यरत न होने के कारण अभी यह कच्चा रोड़ उनकी लीज के पास निकल रहा है तथा वास्तविक रूप से 10 मीटर दूरी पर है । समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि चूॅकि वर्तमान परिस्थिति में कच्चा रोड़ विद्यमान है, अतः कच्चे रोड़ से के पास वाले 7.5 मीटर बैरियर जोन में सबसे पहले तीन कतारों में वृक्षारोपण किया जाये तथा उनके पास ही साइट आफिस व अन्य सुविधाओं का विकास किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे : विद्यालय हेतु वाटर फिल्टर, हेण्डपंप, कुर्सी, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन कि खनिज परिवहन हेतु 40 टन क्षमता के ट्रक का उपयोग किया जावेगा, ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि चारागाह विकास का कार्य ग्राम पंचायत या वन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. खनिज का परिवहन 40 टन क्षमता के ट्रक से किया जावे ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.46 लाख एवं रिक्ररिग 06.31 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)

1	Covid awarness program and disrtibution of mask, sanitizer and handwash.	7,000
2	Provision of one Handpump and Two Water Filter in Primary School, village Kharag.	43,000
3	Provision of 20 Tables and Chairs in Primary School, village Kharag.	30,000
	Total CER Cost	**80,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2500 वृक्षो का वृक्षारोपण :—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॅा	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशू, नीम, पीपल, बरगद, करंज, खमेर, चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॅा ।	1580
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्रनजीवा, मौलश्री, कदंब, नीम, पीपल, बरगद, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॅा, ट्री–गार्ड के साथ ।	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॅा ।	700
4	विद्यालय मे	कदम, नीम, कचनार, गुलमोहर, अशोका, पुतरनजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॅा ।	20
		योग	2500

2. <u>प्रकरण क्रमांक 8272/2021 – मेसर्स करम चंद्र एसोसियेट, श्री संदेश कुमार जैन, सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.) लाईमस्टोन माइन, खसरा नं. 75/1पी, 75/2पी, 74पी, 100पी, 103/1पी, 103/2पी, 103/3पी, 134पी, 135पी, रकबा 26.570 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5,00,940 टीपीए, ग्राम पहरहाई, तहसील विजयराधोगढ जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । **EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.**</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 75/1पी, 75/2पी, 74पी, 100पी, 103/1पी, 103/2पी, 103/3पी, 134पी, 135पी, रकबा 26.570 हेक्टेयर, ग्राम पहरहाई, तहसील विजयराधोगढ जिला कटनी (म.प्र.) पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 489वीं दिनांक 12/03/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र (30 मीटर), उत्तर दिशा में (60 मीटर) तथा दक्षिण–पूर्वी दिशा में (140 मीटर) पर आबादी है । इसी प्रकार उत्तर दिशा में 140 मीटर, दक्षिण दिशा में 160 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 140 मीटर रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रकरण लाईम स्टोन माइनिंग का है, जिसमें आबादी इत्यादि से 50 मीटर की दूरी एम.सी.आर. 2016 छोड़ने का प्रावधान है फिर भी इस प्रकरण में 70 मीटर का सेट–बैक आबादी से प्रस्तावित किया गया है । प्रकरण के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में 03 पिट हैं, जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह पुराने माइंड–आउट पिट है, क्योंकि इस खदान में 1978 से 2002 तक उत्खनन् कार्य किया गया है तथा 2002 से खदान बंद है । चर्चा के दौरान समिति ने यह भी सुझाव दिया कि उत्खनन् एवं वृक्षारोपण हेतु पानी का उपयोग जो पानी पिट में जमा है, उसका उपयोग किया जाये तथा पीने का पानी की व्यवस्था पंचायत की अनुमति प्राप्त कर की जाये ।

समिति द्वारा यह भी पाया गया कि खदान के उत्तर दिशा में स्थित पिट के ऊपर कई वृक्ष है, जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इन वृक्षों को नहीं काटा जायेगा क्योंकि यह सभी वृक्ष आबादी के कारण छोड़े जा रहे 70 मीटर के नॉन–माईनिंग जोन में है । समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार को यह निर्देशित किया कि इस खदान के नॉन–माईनिंग जोन में में प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रथम तीन वर्ष में ही किसी अनुभवी शासकीय संस्था या एजेंसी के माध्यम पूर्ण किया जाये तथा बरसात में नीम की बीजों को रोपित किया जाये, ताकि हरित पट्टिका का विकास हो सके जिससे आबादी एवं ग्रामीण क्षेत्र पर खनन् का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ पुनरीक्षित सरफेस मेप – 70 मीटर सेट–बैक के साथ ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ पुनरीक्षित गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./सी.ई.आर. योजना ।

✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि चारागाह विकास का कार्य ग्राम पंचायत या वन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन–5,00,940 टन प्रति वर्ष।
2. आबादी से 70 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाये ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 41.77 लाख एवं रिक्ररिग 23.42 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.40 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1	Covid awarness program and disrtibution of mask, sanitizer and handwash.	10,000
2	Provision of two Handpumps in village Salaiyapaharhai and health Checkup Camp.	1,00,000
3	Provision of Poshan Aahar in Anganwadi.	1,00,000
3	Provision of 20 Tables and Chairs in Primary School, village Kharag.	30,000
	Total CER Cost	**2,40,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 32,000 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन एवं नॉन–माइनिंग जोन	शीशू, नीम, पीपल, बरगद, करंज, जंगल जलेबी, आम, खमेर, करंज, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	24,450
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, नीम, अमलतास, खमेर, करंज, शीशू, शीशम, पीपल, बरगद, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ।	3,300
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	4,200
4	विद्यालय मे	कदम, अमलतास, नीम, कचनार, गुलमोहर, पुतरनजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	50
		योग	32,000

3. <u>प्रकरण क्रमांक 8292/2021 – श्री प्रदीप सिंह चौहान, एमआईजी–2/12, जैन मंदिर के पीछे, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वाट्ज माइन, खसरा</u>

नं. 621, 634, 635, 636, 637, 638 रकबा 2.911 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्ट्ज–23546 मी.^{3},(62396 टन/वर्ष) ग्राम भदवार, तहसील वाड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow, U.P.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल **खसरा नं.** 621, 634, 635, 636, 637, 638 रकबा 2.911 हेक्टेयर, ग्राम भदवार, तहसील वाड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 424वीं दिनांक 12/02/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्वी दिशा में 55 मीटर की दूरी पर आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रकरण डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्ट्ज माइनिंग का है, जिसमें आबादी इत्यादि से 50 मीटर की दूरी एम.सी.आर. 2016 छोड़ने का प्रावधान है तथा इस प्रकरण में प्रमुखतः उत्खनन् रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जाता है। ब्लास्टिंग की आवश्यकता कभी–कभार ही होती है । समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि चूँकि खदान के पास में आबादी है, अतः उत्खनन् के दौरान प्रमुखतः रॉक–ब्रेकर का ही उपयोग किया जाये तथा खदान के चारों चेन–लिंग फेंसिंग की जाये।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में 02 पिट हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह पुराने माइंड–आउट पिट है, क्योंकि इस खदान में 2013 तक उत्खनन् कार्य किया गया है तथा 2013 से यह खदान बंद है। चर्चा के दौरान समिति ने यह भी सुझाव दिया कि उत्खनन् एवं वृक्षारोपण हेतु पानी का उपयोग जो पानी पिट में जमा है, उसका उपयोग किया जाये तथा पीने का पानी की व्यवस्था पंचायत की अनुमति प्राप्त कर की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैस : स्कूल का सृदृढीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कैंप, ऑगनवाडी की मदद इत्यादि) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । चर्चा के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह अवगत कराया गया कि जनसुनवाई

के दौरान ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें पड़ने की सूचना ग्रामीण द्वारा दी गई है । ततसंदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनकी खदान 2013 से बंद है तथा उत्खनन् के दौरान वे रॉक–ब्रेकर का उपयोग करेंग जिस संदर्भ में समिति द्वारा उनको लिखित बचन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. / सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि उत्खनन् का कार्य रॉक–ब्रेकर से किया जायेगा तथा किसी भी पेड़ को नहीं काटा जायेगा।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि 2013 से आज दिनांक तक उत्खनन् का कार्य बंद है ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि खदान के चारों ओर चेन–लिंक फ्रेसिंग की जावेगी तथा पीने हेतु पानी ग्राम पंचायत की अनुमति के पश्चात् लिया जावेगा ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि खदान के पूर्वी दिशा में स्थित आवासीय क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी तक कोई खनन् कार्य नहीं किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वाट्ज –23546 मी.3 (62396 टन / वर्ष) प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.50 लाख एवं रिकरिंग 05.62 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1	Organize Health Chechup Camp in Village.	10,000
2	Provision of Poshan Aahar and Whitewash in Anganwadi.	1,30,000
3	Provision of Whitewash, School Bags and Books in Primary School.	60,000
	Total CER Cost	**2,00,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3494 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	इमली, कैथा, ऑवला, नीम, पीपल, करंज, जंगल जलेबी, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1500
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्रनजीवा, मौलश्री, कदंब, कटंग बॉस, मुनगा, शीशम, कैथा, नीम, पीपल, करंज, जंगल जलेबी, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	524
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, महुआ, बेल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1440
4	विद्यालय मे	कदम, नीम, कचनार, गुलमोहर, पुतरनजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	30
		योग	3494

4. <u>प्रकरण क्रमांक 8967/2022 – श्री सुधांशु गुप्ता, 2382, राईट टाऊन तहसील एवं जिला जबलपुर स्टोन एवं मुरूम क्वेरी, खसरा नं. 24/2 पार्ट, रकबा 1.80 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 15,000 मी.^{3} एवं मुरूम – 7056 मी.^{3} ग्राम मानेगांव तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल **खसरा नं. 24/2 पार्ट, रकबा 1.80 हेक्टेयर, ग्राम मानेगांव तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.)** पर स्थित है ।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 2257 दिनांक 16/11/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 18 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 35.09 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान 02 भागों में स्वीकृत होना पाया गया तथा खदान के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 245 मीटर पर आबादी है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.

आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर–पूर्वी दिशा में 240 मीटर दूरी पर आबादी है, जिसकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 18 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) से प्राप्त हुई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

5. <u>प्रकरण क्रमांक 8970/2022 – श्री सुधांशु गुप्ता, 2382, राईट टाऊन तहसील एवं जिला जबलपुर स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 24/2 पार्ट, रकबा 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,000 मी.^{3} ग्राम मानेगांव तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>
<u>EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 24/2 **पार्ट**, रकबा 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,000 मी.^{3} ग्राम मानेगांव तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) पर स्थित है ।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 3227 दिनांक 16/11/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 18 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 35.09 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 300 मीटर पर आबादी है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर–पूर्वी दिशा में 300 मीटर दूरी पर आबादी है, जिसकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 18 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) से प्राप्त हुई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

6. <u>प्रकरण क्रमांक 8971/2022 – मेसर्स प्रभात तिवारी, ओनर श्री प्रभात तिवारी, जगमोहन दास वार्ड, नई वस्ती, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट माईन, खसरा नं. 74 (नया खसरा नं. 137), रकबा 2.084 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 61,803 मी.^{3} ग्राम मानेगांव तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । **M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल **खसरा नं. 74 (नया खसरा नं. 137), रकबा 1.00 हेक्टेयर, ग्राम मानेगांव तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.)**पर स्थित है ।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 4893 दिनांक 23/09/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 17.764 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर–पश्चिम दिशा में 25 मीटर पर जल भराव क्षेत्र है तथा कुछ वृक्ष लीज एरिया में परिलक्षित हो रहे है । इसके साथ–साथ एक कच्चा रोड़ भी लीज एरिया से निकल रहा है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 25 मीटर पर जल भराव क्षेत्र है, जिसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. खदान में कुछ वृक्ष परिलक्षित हो रहे है, जिनकी इंवेंट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

3. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित होने समस्त खदानों का ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

7. **<u>प्रकरण क्रमांक 8965/2022 – श्री संजय त्यागी, 107 राज इनक्लेब, आदित्यपुरम, तहसील गिर्द जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्वाईल क्वेरी, खसरा नं. 284, 285, 293, 294, रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2500 मी.^{3}, ग्राम बिलगांव चौधरी, तहसील जौरा जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्। EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 284, 285, 293, 294, रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2500 मी.^{3}, ग्राम बिलगांव चौधरी, तहसील जौरा जिला मुरैना (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1088 दिनांक 02/09/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है । अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 150 मीटर पर पक्का रोड़, उत्तर दिशा में 50 मीटर पर कच्चा रोड़ पर होना परिलक्षित हो रहा है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि खदान में 02 मीटर से अधिक उत्खनन् नहीं किया जायेगा तथा कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि खदान क्षेत्र में चिमनी की स्थापना नहीं की जावेगी ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/2/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य

होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाइल–2500 मी.^{3}-प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.24 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.99 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1.	Poshan Aahar in Anganwadi	60,000
	Total CER Cost	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1200 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	शीशू, नीम, पीपल, पुत्रनजीवा, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
2.	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, नीम, बरगद, अमलतास, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	400
3.	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आम, ऑवला, मुनगा, कटहल, अमरूद, इमली, नीबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
		योग	1200

8. <u>प्रकरण क्रमांक 8951/2022 – श्रीमती लाटूवाई मेवाड़ा, पट्टाधारी, ग्राम भेंसरोद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1816/1, 1816/2 1804, 1828 रकबा 1.73 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–8,000 मी.^{3}, ग्राम भेंसरोद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1816/1, 1816/2 1804, 1828 रकबा 1. 73 हेक्टेयर, ग्राम भेंसरोद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की

एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1174 दिनांक 01/10/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है । अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 125 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित हो रहा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुए है जिसके सदंर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेड़ों के उत्तर–पश्चिम दिशा में 15 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जायेगा तथा कोई भी पेड़ नहीं काटा जावेगा । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –8,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.41 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1.	Poshan Aahar in Anganwadi	60,000
	Total CER Cost	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2100 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1.	बैरियर जोन	शीशू, नीम, पुत्रनजीवा, करंज, चिरोल, जंगलजलेबी, आंवला, सीताफल,कदम, कटंग बॉस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000
2.	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, करंज, कचनार, आम, इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	200
3.	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	सीताफल, पपीता, हाईब्रिड अमरूद, आम, ऑवला, मुनगा, कटहल, इमली, नीबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	900
		योग	2100

9. प्रकरण क्रमांक 8966/2022 – श्री ललित कुशवाहा, कैठ का पूरा, कोडेरा तहसील – कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 553 रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–10,290 मी.^{3}, ग्राम कैठ का पूरा, कोडेरा तहसील – कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 553 रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–10290 मी.3, ग्राम **कैठ का पूरा**, कोडेरा तहसील – कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 885 दिनांक 06/08/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 2.0 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 60 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित हो रहा है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–10,290 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1.	Poshan Aahar in Anganwadi	60,000
	Total CER Cost	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1200 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	आम, शीशू, नीम, कदम, करंज, चिरोल, इमली, आंवला, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	700
2.	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, मुनगा, सीताफल, करंज, कचनार, आम, इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	200
3.	ग्राम पंचायत भवन	नीम, पीपल, करंज, खमेर, कचनार, गुलमोहर, पाकड़, बकान, ऑवला, सीताफल, अमरूद, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
		योग	1200

10. <u>प्रकरण क्रमांक 8969/2022 – मेसर्स बाबा मिनरलस, प्रो. श्रीमती खुशबू गोयनका, वार्ड न. 6, विजूरी, तहसील – कोतमा जिला – अनूपपुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 26, रकबा 1.619 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 5993 मी.^{3}, ग्राम डोगारिया खुर्द तहसील – कोतमा जिला – अनूपपुर (म.प्र.) के प्र्यावरणीय स्वीकृति बावत् । **Env. Consultant – Atmos Sustanable Solutions (P) Ltd., Noida (U.P.)**</u>

राज्य स्तरीय प्र्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित सिलि खसरा नं. 26, रकबा 1.619 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्ओन– 5993 मी.^{3}, ग्राम डोगारिया खुर्द तहसील – कोतमा जिला – अनूपपुर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन ाखा) पत्र क्रमांक 132 दिनांक 02/07/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 4.485 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान सिल के उत्तर पश्चिमी दिशा में 70 मीटर पर प्राकृतिक जल संरचना होना परिलक्षित हो रहा है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा अवगत कराय गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा भरे गये फार्म–2 में कुछ गल्तियॉ है, जिनको सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि खदान क्षेत्र में कुल 05 वृक्ष लगे हुए है तथा खनन् के दौरान इन 05 में से 01 वृक्ष को काटा जाना प्रस्तावित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस काटे जाने वाले 01 वृक्ष के एवज में 10 अतिरिक्त वृक्ष लगायेंगे । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ परियोजना प्रस्तावक द्वारा भरे गये फार्म–2 में कुछ गल्तियॉ है, जिन्हें सुधार कर प्रस्तुत किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/2/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतो ाजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतो ाजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशि ट ार्तो एवं स्टेण्डर्ड ार्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5993 मी.^{3} प्रति व ा।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1.	Poshan Aahar in Anganwadi	70,000
	Total CER Cost	**70,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2010 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	सीरस, रीठा, बॉस, खमार चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1110
2.	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, खॉखर, चिरोल, करंज, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	300
3.	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, ऑवला, सीताफल, अमरूद, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
4.	कनाई नाले के सामानांतर	कटंग बॉस, खसघॉस, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
		योग	2010

11. Case No. - 5591/2017 M/s Dhruv Construction, Plot No. A, 21, Swastik Green City, District - Shahdol, MP – 484001 (SIA/MP/MIN/70635/2017) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 6.0 Ha.. (1,15,000 cum per annum) (Khasra no. 18/1 (P)) at Village- Dholar, Tehsil - Jaisinghnagar, Dist. Shahdol (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra no. 18/1 (P) at Village- Dholar, Tehsil - Jaisinghnagar, Dist. Shahdol (MP) 6.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted following details:

- It is Dholar Stone Quarry project covers an area of 6.00 hectares for mining of minor mineral at village-Dholar, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol, and Madhya Pradesh.
- Previouslt, EC was recommended in 303 SEAC meeting dated 23-12-17.
- EC granted in 470 SEIAA meeting dated 22-02-18. EC issued vide letter no. 1960-61/SEIAA/18 dated 14-03-18.

- We have applied for amendment in Environmental Clearance of Dholar Stone Quarry, at Khasra no. 18/1 in Village- Dholar, Tehsil- Jaisinghnagar, Dist.- Shahdol (M.P.), area-6.0 ha for amending the production of next of five year (9793 cum/yr) as per the approved mining scheme in line with the production of first five years (1,15,000 cum/yr).
- At the time of applying for the prior application of EC we have filled the production capacity of both 1st five year and 2nd five year as per the approved mining plan but as per the MMR rule 1996 initial mining plan was approved only for the production of 1st five year.
- It is kindly requested that on the basis of the submitted approved mining scheme & documents, kindly do the amendment in the prior EC issued by SEIAA in (EC) No. 1960 dated 14-03-2018 by adding the production capacity of the 2nd five years as per the approved mining scheme in line with the production capacity of 1st five year.
- PP submitted that under CER following activities have been conducted byb them and having bills as a proof:
    - ✓ We have provided food and raw materials to the nearby villagers during the Covid -19 pandemic.
    - ✓ We have repaired the boundary wall of the Aamanar higher secondary school and aaganwadi Kendra of Jaysinghgar.
    - ✓ We have repaired the boundary wall of the Aamanar higher secondary school and aaganwadi Kendra of Jaysinghgar.
- PP further submitted that they are regularly submitting the six monthly compliance reports to the SEIAA which is being uploaded on their website.

During appraisal of the case and compliance of the EC conditions, it was observed by the committee that as per the earlier EC three row plantations was to be carriedout by the PP but as per the photographs submitted by PP, only one row plantation could be seen along the boundary wall which shows negligence of the PP towards green belt development. PP submitted that they have carriedout plantation but it’s true that the plantation along the boundary wall is in single row and thsy have not read the Ec conditions carefully that that’s why this mistake is happned. Committees after deliberations recommends that within 30 days PP shall carryout three row plantation along the boundary wall as per the EC conditions and submit credible proof to SEIAA as a part of previous EC compliance report for consideration of amendment.
Committee asked PP and their consultant the explain what amendment they are seeking and why. PP submitted that:

- Prior EC was issued by MP SEIAA vide letter no. 1960/SEIAA/18 dated 14-03-2018 for the production of crusher stone with capacity 1,15,000 cum/yr (for first five years) & 9763 cum/yr (for next five years), here we are applying for EC amendment to amend the production capacity of next five year as per the revised mining scheme in line with the production capacity of 1st five year as per the approved mining plan.

- The revised mining scheme has been approved by Directorate of Geology & mining, Regional Office Rewa vide letter no. 1387/2021 dated 25/11/2021 & the prior mining plan has been approved by Directorate of Geology & mining Regional Office Rewa vide letter no. 1152 dated 24/07/2017. The D'rate of Geology & Mining Bhopal MP sanctioned the lease Vide order No.-3020/khanij/F.No.-1/Q.L./ 2017/, Bhopal Dated 09/03/2017.

- At the time of applying for the prior application of EC we have filled the production capcity of both 1st five year and 2nd five year as per the approved mining plan but as per the MMR rule 1996 initial mining plan was approved only for the production of 1st five year. It is kindly requested that on the basis of the submitted approved mining scheme & documents, kindly do the amendment in the prior EC issued by SEIAA in (EC) No. 1960 dated 14-03-2018 by adding the production capacity of the 2nd five years as per the approved mining scheme in line with the production capacity of 1st five year.

After presentation committee asked PP to submit following details:-

- Commitment of PP that three rows plantation will be completed within next 30 days and compliance report will be submitted to SEIAA.
- Revised CER as suggested by committee.

PP submitted the above commitment and reply vide letter dated 17/02/22 which was placed before the committee and found satisfactory and acceptable. The committee after deliberations recommends that only after verifiable and credible compliance report to SEIAA amendment in EC may be considered for production of Stone in an area of 6.0 Ha. Capacity 1,15,000 cum per annum as per revised mining scheme at Khasra no. 18/1 (P) at Village- Dholar, Tehsil - Jaisinghnagar, Dist. Shahdol (MP). The other conditions issued in previous EC (Issued vide letter no. 1960-61/SEIAA/18 dated 14-03-18) shall remain unchanged.

12. Case No 8649/2021 M/s Akash Granite, Prop. Shri Dinesh Chandra Gupta, Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Environment Consultant : Globus Environment Engineering Service, Lucknow.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by Env. Consultant Shri Anand Gupta on behalf of PP from M/s. Globus Environment. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office letter No. 2474 dated 29/7/21 has reported that there are 06 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 19.105 ha., including this mine. Within 500 meters following sensitive features were observed of the lease area:

Sensitive Features	Approximate aerial distance from the lease area in meters	Direction
Water body	>120	South- East
Pucca Road	900	North –West

The Committee further observed that the on-line mine plan maps are not uploaded on the Parivesh Portal by PP. During appraisal it was observed by committee that lease area is already mined out since 2017 and lease was also allotted to the PP in the year 2017. PP submitted that after allotment of lease case was filled in the court of law and was decided in the year 2020 and they have not carried out mining in the area. Committee after deliberation decided that PP shall submit M.O. clarification regarding existing mined out pit in the lease area for further consideration.

प्रकरण आज दिनांक 17/02/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा इस प्रकरण में परियोजना

प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण अंतिम अवसर प्रदान करते हुए हेतु प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा फिर भी यदि परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहता है तो यह प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

13. Case No. – 6576/2019 M/s Pacific Industries Ltd, Village - Chilpi, Tehsil & Dist. Anuppur, MP. Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 3.816 ha. (7,500 cum per annum) (Khasra No. 2610), Village - Chilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP).

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2610), Village - Chilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 3.816 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted following details:

- Initially our case was recommended in 461st SEAC meeting agenda dated 29-09-2020
- EC granted in 643th SEIAA meeting dated 06-10-2020.
- EC issued vide letter no. 4561-62/SEIAA/20 dated 29-10-2020.
- Reason for amendment: We have now applied for the EC amendment to add the capacity of Stone waste as the (sealable stone waste 22,500 max cu.mt/yr as per the approved mining plan) production in previous issued EC vide letter no. 942 dated 02-06-2018.

PP further submitted that:

- The present production capacity as per the previous issued EC by SEIAA is 7500 cu.mt/yr Granite Block (25% of total production) & the remaining 75% is stone waste which is not mentioned in EC but it is the part of the total mineral excavated.
- Therefore the mineral excavated remains same however the stone waste (max 22,500 cu.mt/yr) is now proposed for sealable stone waste for crusher stone purpose.
- In such case the predicted pollution load due to excavation remains the same as previous. Hence there will be no increment in the pollution load due to

excavation. The only anticipated increase will be through transportation of mineral as number of trips will be increased.

- Presently only granite block is being transported and 2 number of dumper was required per day. With proposed amendment, stone waste will also transported which requires 2 more number of dumper with 10 trips (one side).
- Hence the total number of dumper requires will be 10 per day.
- Details in tabular for is provided in next slide.

Existing as per previous EC production	
Daily Production - Assuming 300 working days (8 hours in day)	~25 m^3
Total number of trips required (One Side)	4
Total dumper required (6-8 m^3 capacity)	2 nos dumper

After adding the Stone Waste	
Daily Production - Assuming 300 working days (8 hours in day)	~100 m^3
Total number of trips required (One Side)	10
Total dumper required (10 m^3 capacity)	4 nos dumper

During appraisal of the case and compliance of the EC conditions, it was observed by the committee that as per the earlier EC three row plantations was to be carriedout by the PP but as per the photographs submitted by PP, only one row plantation could be seen along the boundary wall which shows negligence of the PP towards green belt development. PP submitted that they have carriedout plantation but it’s true that the plantation along the boundary wall is in single row and thsy have not read the Ec conditions carefully that that’s why this mistake is happned. Committees after deliberations recommends that within 30 days PP shall carryout three row plantation along the boundary wall as per the EC conditions and submit credible proof to SEIAA as a part of previous EC compliance report for consideration of amendment.

After presentation committee asked PP to submit following details:-

- Commitment of PP that three rows plantation will be completed within next 30 days and compliance report will be submitted to SEIAA.

- Commitent for 5000 numbers of plantations on revenue land competent authority.
- Commitent for proper barbed wire fencing as per mine closure plan.
- Revised CER as suggested by committee.

PP submitted the above commitment and reply vide letter dated 17/02/22 which was placed before the committee and found satisfactory and acceptable. The committee after deliberations recommends the case for amendment in EC for sealable stone waste 22,500 cu.mt/yr in an area of 6.0 Ha in an area of 3.816 ha. with Granite 7,500 cum per annum at Khasra No. 2610, Village - Chilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP). The other conditions issued in previous EC (Issued vide letter no. 4561-62/SEIAA/20 dated 29-10-2020 shall remain unchanged.

14. <u>Case No. – 6361/2019 Shri Ashok Vishwakarma, Jalpa Ward, Gautam Lane, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Soil Laterite and Fireclay Mine in an area of 5.360 ha. (Laterite - 16526 Tonne Per Annum and Fireclay - 2636 Tonne Per Annum) (Khasra No. 04), Village - Mohla, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur</u>

This is case of Soil Laterite and Fireclay Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 04), Village - Mohla, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur 5.360 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter No. 504 dated: 02/05/19 has reported that there is 02 more mine operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 16.621 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 379th SEAC dated 04/07/2019 wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA report vide letter dated 02/2/2021 which was forwarded through SEIAA vide letter no. 7276 dated 15/3/2021, which was placed before the committee.

The case was scheduled again for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to

make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. PP was also absent in the 493rd meeting dated 23/3/2021 & 491st meeting dated 18/03/2021. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project.

प्रकरण आज दिनांक 17/02/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण अंतिम अवसर प्रदान करते हुए हेतु प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा फिर भी यदि परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहता है तो यह प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

15. <u>Case No 8841/2021 M/s Arcon Mining Pvt. Ltd, Flat No. 101, Virendra Villas Apartment, Patel Nagar, Dist. Gwalior, MP - 474001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.090 ha. (12000 Cum per annum) (Khasra No. 2627/min-1, 2630/min-2&3, 2632/min-2&3, 2633, 2634/1-min2), Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) RQP Swati Namdeo, Bhopal</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2627/min-1, 2630/min-2&3, 2632/min-2&3, 2633, 2634/1-min2), Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was again scheduled for the presentation in 534th SEAC meeting dated 15/12/21 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings.

The case was scheduled again for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation.

PP was also absent in the 538th SEAC meeting dated 6/1/22 & 534th SEAC meeting dated 15/12/21. Committee decided to give last chance to PP for making presentation

in the subsequent meetings of SEAC after which the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

आज दिनांक 17/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 10 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 05 मीटर पर कच्चा रोड़ है जिमसें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दोनों ही ओर से रोड़ 10 मीटर से अधिक दूरी पर है तथा 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ने पर लगभग 17 मीटर की दूरी हो जायेगी । चर्चा के दौरान समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशि किया कि किसी भी परिस्थिति में कच्चे रोड़ से कम से कम 10 मीटर की दूरी प्रतिबंधित रखी जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि खदान 02 भागों में हैं जिसमे संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एक हेक्टेयर का एरिया पूर्ण करने के लिए खदान 02 भागों स्वीकृत की गई है तथा दूसरे छोटे भाग में उनके द्वारा उत्खनन् नहीं किया जावेगा साईट व ग्रीन बेल्ट का विकास किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 05 पेड़ हैं, जो सभी बैरियर जोन या नॉन–माइनिंग एरिया में होने के कारण काटे जाने कोई प्रस्ताव नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–12000 मी.^{3}-प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.56 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1.	Poshan Aahar in Anganwadi	1,00,000
	Total CER Cost	**1,00,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1400 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	रीठा, चिरोल, बॉस, खमार, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	700

2.	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, कचनार, करंज, चिरोल, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	200
3.	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	सीताफल, आम, ऑवला, मुनगा, कटहल, अमरूद, इमली, नीबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
		योग	1400

16. <u>Case No. – 6528/2019 Shri Altaf Kha, Jirapur, Tehsil - Jirapur, Dist. Rajgarh, MP - 465661. Prior Environment Clearance for Basalt Stone quarry in an area of 2.00 ha. (2,850 cum per annum) (Khasra No. 1127/1/1), Village - Khilchipur, Tehsil - Khilchipur, Dist. Rajgarh (MP).</u>

यह प्रकरण सिया के पत्र क्रमांक 2951 दिनांक 27/01/22 द्वारा रिलिस्ट कर एसईएसी को परीक्षण हेतु भेजा गया । समिति द्वारा यह पाया गया कि इस प्रकरण पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सेक की 402वीं बैठक दिनांक 05/11/19 के माध्यम से सिया को प्रेषित की जा चुकी है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस प्रकरण से संबंधित नस्ती सिया को आगामी कार्यवाही वापिस प्रेषित की जाये ।

(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव	(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing

species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.